

मणिपुर में माफी कोरा दिखावा न होकर सार्थक बदलाव करें



ललित गर्ग

मणिपुर में जातीय संघर्ष, व्यापक हिंसा एवं अराजक माहौल के लिए पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बीते साल को आखिरी दिन शायदी में एक सगड़ी नीय पहल करते हुए हाँ। हामाफील मांगी है, इस माफी को लेकर राजनीति के गलियोंमें व्यापक चर्चा है। क्योंकि इस हिस्से में मई 2023 से 250 से अधिक लोगों को जन चर्चा गई और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लखे

समय से यह प्रांत अस्थिरता, असंतोष एवं अशांति का आग में जल रहा है। एन बीरेन सिंह ने माफी मांगते हुए हिस्से के इस लंबे कालखण्ड एवं सिलसिले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सभी समुदायों से अपील की कि पिछले गलतियों को भुलाकर वे शांति और सौहार्द कायम करें। हालांकि मुख्यमंत्री की इस अपील के अन्ते मतलब निकाल जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह माफी बहुत पहले मांगी जानी चाहिए थी। कुछ का यह माना है कि माफी ऐसे समय अर्थात् है कि जब मुख्यमंत्री चौराफा दबाव में है। विधायी तो बहुत लंबे से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, पिछले कुछ समय से खुद उनके विधायिकों और सहयोगियों ने इस माफी को उनकी मजबूरी की ओर से सभी 70 सीटों पर लाने की संभावना है। इसके लिये विधायिकों के चयन की निश्चित ही बीरेन सिंह के लिये माफी मांगना काफी नहीं है, अगर वह मानते हैं कि स्थिति को संभालने में नाकाम रहे तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था। केन्द्र को राष्ट्रीयता शासन लगाना चाहिए था। अफसोसनाक यह है कि इस मसले पर अक्षर विवाद उभरते रहे और राजनीतिक शाखियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप अक्सर बेलगाम बोल में तब्दील ही होते रहे, कोई ठीक समाधान साने नहीं आया, जो गैरिजमेदाराना राजनीति को दर्शाता है।

मणिपुर में 3 मई 2023 से ही बहुसंख्यक मैत्रैई और कुकी के बीच आरक्षण और आर्थिक लाभ को लेकर जो हिंसा शुरू हुई वह अभी थमने का नाम नहीं ले रही। कभी अपनी सांस्कृतिक सन्दर्भाना के लिए जाना जाने वाला राज्य अब गहराते विभाजन पर जातीय संघर्ष का सामना कर रहा है और कुछ लोग लगातार भय में जी रहे हैं। तानाव का होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा। राजित एवं सद्दर्भाना की तलावरा अभी भी जारी है। मणिपुर में जब चंद दर्वाजे दो भालूओं के निवास कर उनके साथ बर्बादापूर्ण हरकत करते रहते नजर आए तो पूरा प्रांत आक्रोश में आ गया। जननामास की प्रतिक्रिया लोकान्त्रिक व्यवस्था में बहुत महत्व रखती है। न तो राज्य सरकार ने और न ही केन्द्र सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कोई ठोस उपयोग किए और न ही शांति स्थापित करने के कोई प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री एन बीरेन सरकार डेढ़ साल से ज्यादा समय से खेड़ों में बंटी राजनीति के उलझन में फंसी ही। सभी दल, नेता एवं सरकार नायुमिन निशानों की ओर पूरी अपनी चाही रही है। यह कौमों के साथ नायुमिनी होने के साथ अमानवीयता की चार्चा पराकारा थी। क्योंकि ऐसी दौड़ जहां पहुंच चाही है, वहां कम्पयाची की मजिल नहीं, बल्कि मायूसी का गहरा गङ्गा होता है।

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह स्वीकारोक्ति कि हाँहामैं राज्य में जो कुछ हुआ उसके लिए खेद व्यक्त करना चाहता हूँ। कई लोगों ने अपनों को खो दिया और कई लोगों को अपना घर छोड़ा पड़ा। मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आम प्रांती की व्यापक मांगता हूँ। लेकिन पिछले तीन-चार महीनों में अपेक्षाकृत शांति देखने के बाद, मुझे उम्मीद है कि आगे वाले लाल में स्थिति सामान्य हो जाएगी। हिंसा में बहुत महत्व रखती है। इसीलिये विपक्ष दल एवं कांग्रेस उन पर और केन्द्र सरकार पर हमलावर है। 19 महीनों में एन बीरेन असंवेदनशील बने रहे और अब वर्ष के अंत में उन्होंने अपनी मांगकर किस संवेदनशीलता का परिचय किया है? अब सबाल यह है कि त्रासदी का अंत कैसे होता है? कैसे शांति स्थापित होती है? जरूरत है मनुष्य को बांधनी, सत्य को ढूकें।

फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ, पार्टी अपनी नीतियों में जनता के विवास को फिर से बनाने और अपने शासन रिकॉर्ड और विवादों

दिल्ली चुनाव में भाजपा व आप की सीधी लड़ाई में मायावती का हाथी किसका खेल बिगड़ेगा?



अशोक भाद्रव

से आकर लेने वाले राजनीतिक परिवहन के नेतृत्व करने के लिए टूट संकलित है। 2024 में आप के लिए सभी बड़ी झटके के पूर्व मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल की मार्च में प्रवर्तन दिल्ली द्वारा उत्पादित श्रावण शुक्रवार नीति मामले से जुड़े कथित प्रधाचार को लेकर गिरफतारी थी। यह पहली बार था कि किसी भौजूद मुख्यमंत्री को गिरफतार किया गया।

मई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिया जाने से पहले केजरीवाल ने लगभग छह महीने तिहाड़ जेल में बिताया। जबकि अदालत ने उन्हें लोकसभा चुनावों के बीच सीधी लड़ाई करने के लिए प्रचार करने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनावों के लिए जब राजनीतिक विधायिकों की विधायिकों की विधायिकों से जुड़े कथित प्रधाचार को लेकर गिरफतारी थी। यह पहली बार था कि किसी भौजूद मुख्यमंत्री को गिरफतार किया गया।

ऐसे में भाजपा जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सातों सीटों जीती थी अब इस चुनाव में आप की पार्टी की ज्ञाना पर सभी बालों के लिए गिरफतार किया गया। जेल से बाहर आने के लिए जीत का इस रण में अचानक बसपा ने सभी सीटों पर लड़ाई की ओर आया। यह एसी बहुल क्षेत्रों में सजातीय प्रत्यावर्ती को लिये जाना चाहिए। इसके बाद उत्तरांक विधायिकों की विधायिकों से जुड़े कथित प्रधाचार को लेकर गिरफतार किया गया।

मई में भाजपा जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सातों सीटों जीती थी अब इस चुनाव में आप की पार्टी की ज्ञाना पर सभी बालों के लिए गिरफतार किया गया। जेल से बाहर आने के लिए जीत का इस रण में अचानक बसपा ने सभी सीटों पर लड़ाई की ओर आया। यह एसी बहुल क्षेत्रों में सजातीय प्रत्यावर्ती को लिये जाना चाहिए। इसके बाद उत्तरांक विधायिकों की विधायिकों से जुड़े कथित प्रधाचार को लेकर गिरफतार किया गया।

आप के राज्यसभा संसद संघर्ष सिंह के अंत्रैल के जैसा नियम गई, पूर्व उत्पादित भौजूद मायावती की विधायिकों के साथ-साथ अन्य विरष्ट कर उत्तरांक ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यह एसी बहुल क्षेत्रों में सजातीय प्रत्यावर्ती को लिये जाना चाहिए। इसके बाद उत्तरांक विधायिकों की विधायिकों से जुड़े कथित प्रधाचार को लेकर गिरफतार किया गया।

दिल्ली विधायिकों के लिए जीत का इस रण में अचानक बसपा ने सभी सीटों पर लड़ाई की ओर आया। यह एसी बहुल क्षेत्रों में सजातीय प्रत्यावर्ती को लिये जाना चाहिए। इसके बाद उत्तरांक विधायिकों की विधायिकों से जुड़े कथित प्रधाचार को लेकर गिरफतार किया गया।

जान ही कि लोकसभा चुनाव में बिना गठबंधन में शामिल हुए अंकेल में बैदान में अब चुनाव नीचे गिर रहे बसपा के बोट प्रतिशत इस चुनाव में नहीं जीती रही। इसके बाद उत्तरांक विधायिकों की विधायिकों से जुड़े कथित प्रधाचार को लेकर गिरफतार किया गया।

2024 के लोकसभा चुनावों में, आप के अंत्रैल के जैसा नियम गई, पूर्व उत्पादित भौजूद मायावती की विधायिकों के साथ-साथ अन्य विरष्ट कर उत्तरांक ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यह एसी बहुल क्षेत्रों में सजातीय प्रत्यावर्ती को लिये जाना चाहिए। इसके बाद उत्तरांक विधायिकों की विधायिकों से जुड़े कथित प्रधाचार को लेकर गिरफतार किया गया।

2024 के लोकसभा चुनावों में, आप दिल्ली के जैसा संघर्ष लेने के लिए जीत का इस रण में अचानक बसपा ने सभी सीटों पर लड़ाई की ओर आया। यह एसी बहुल क्षेत्रों में सजातीय प्रत्यावर्ती को लिये जाना चाहिए। इसके बाद उत्तरांक विधायिकों की विधायिकों से जुड़े कथित प्रधाचार को लेकर गिरफतार किया गया।

2024 के लोकसभा चुनावों में, आप दिल्ली के जैसा संघर्ष लेने के लिए जीत का इस रण में अचानक बसपा ने सभी सीटों पर लड़ाई की ओर आया। यह एसी बहुल क्षेत्रों में सजातीय प्रत्यावर्ती को लिये जाना चाहिए। इसके बाद उत्तरांक विधायिकों की विधायिकों से जुड़े कथित प्रधाचार को लेकर गिरफतार किया गया।

2024 के लोकसभा चुनावों में, आप दिल्ली के जैसा संघर्ष लेने के लिए जीत का इस रण में अचानक बसपा ने सभी सीटों पर लड़ाई की ओर आया। यह एसी बहुल क्षेत्रों में सजातीय प्रत्यावर्ती को लिये जाना चाहिए। इसके बाद उत्तरांक विधायिकों की विधायिकों से जुड़े कथित प्रधाचार को लेकर गिरफतार किया गया।

2024 के लोकसभा चुनावों में, आप दिल्ली के जैसा संघर्ष लेने के लिए जीत का इस रण में अचानक बसपा ने सभी सीटों पर लड़ाई की ओर आया। यह एसी बहुल क्षेत्रों में सजातीय प्रत्यावर्ती को लिये जाना चाहिए। इसके बाद उत्तरांक विधायिकों की विधायिकों से जुड़े कथित प्रधाचार को लेकर गिरफतार किया गया।

2024 के लोकसभा चुनावों में, आप दिल्ली के जैसा संघर्ष लेने के लिए जीत का इस रण में अचानक बसपा ने सभी सीटों पर लड़ाई की ओर आया। यह एसी बहुल क्षेत्रों में सजातीय प्रत्यावर्ती को लिये जाना चाहिए। इसके बाद उत्तरांक विधायिकों की विधायिकों से जुड़े कथित प्रधाचार को लेकर ग



बाला सावंत का जन्म दिवस मनाया गया

